# चीन, फ्रॉस, मध्य यूरोप और इटली की तर्ज पर दिल्ली में जलापूर्ति की निगरानी करेगी केजरीवाल सरकार

**नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता**

चीन, फ्रॉस, मध्य यूरोप और इटली की तरह दिल्ली में जलापूर्ति को व्यवस्थित करने को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है, ताकि दिल्ली के सभी इलाकों में जरूरत के अनुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर जलापूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए पूरी दिल्ली में फ्लोमीटर का काम हर हाल 31 दिसंबर तक पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। वहीं, एक जुलाई से दिल्ली जल बोर्ड जलापूर्ति का सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग करना शुरू कर देगा। इसके आधार पर आवश्यकता के अनुसार दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। इस व्यवस्था को लागू होने के बाद दिल्ली के किसी भी इलाके में पानी की अतिरिक्त या कम आवश्यकता होने की सेंट्रलाइज्ड जानकारी मिल सकेगी और इसके आधार पर दिल्ली जल बोर्ड उस इलाके में आवश्यकतानुसार जलापूर्ति को लेकर निर्णय ले सकेगा।

दिल्ली सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीजेबी के अधिकारियों से फ्लोमीटर लगाने की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने पाया कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने कडी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने प्राइमरी और सेकेंडरी यूजीआर पर फ्लोमीटर लगाने की समय सीमा भी तय की, ताकि दिल्ली में पानी की उपलब्धता और सप्लाई की पूरी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध हो। इसके लिए 31 दिसंबर तक दिल्ली जल बोर्ड को बाकी बचे सभी फ़्लोमीटर को लगाने का काम पूरा करना होगा। दिल्ली सरकार स्केडा सिस्टम के तहत दिल्ली में पानी की आपूर्ति को व्यवस्थित करने पर काम कर रही है। चीन, फ्रॉस, मध्य यूरोप और इटली समेत कुछ देशों में स्केडा सिस्टम से वाटर नेटवर्क का प्रबंधन किया जाता है। बैठक में जल मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती और डीजेबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम

अरविंद केजरीवाल हर स्तर पर पानी की बबार्दी रोकने को लेकर गंभीर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उपलब्ध सीमित पानी की हर स्तर पर किसी भी तरह की बबार्दी को रोकने को लेकर बेहद गंभीर हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पानी की एक-एक बूंद को सहेजने पर बल दिया। दिल्ली जल बोर्ड के आंकलन के अनुसार, दिल्ली में उपलब्ध बहुत सारे पानी का कोई लेखा जोखा नहीं है। यह पानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई ती किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के ऑडिट सिस्टम के अंदर पानी नहीं आ पा रहा है। पिछले 20-30 वर्षों के अंदर अलग-अलग कारणों से पानी की जो मुख्य लाइन जाती थी, वहां से पानी की टैपिंग विभिन्न इलाकों में दी गई हैं। इस वजह से कई इलाकों अंदर पानी कम प्रेशर से आता है तो कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच पाता है।

दिसंबर तक सभी प्राइमरी और सेकेंडरी यूजीआर पर लग जाएंगे फ्लोमीटर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर बीते वर्षों में पाइप लाइन के उपर फ्लोमीटर लगाने काम तेजी से आगे बढा है। दिल्ली जल बोर्ड ने अभी तक प्राइमरी स्तर पर करीब 352 फ्लोमीटर इंस्टॉल किया है और करीब 108 फ्लोमीटर इंस्टॉल करने की जरूरत है। इसके अलावा सेकेंडरी मेन वाटर लाइन के 4053 लोकेशन पर फ्लोमीटर लगाने की जरूरत है और अभी तक 2456 पाइप लाइन के उपर फ्लोमीटर लग चुके हैं, जबकि 1537 फ्लोमीटर अभी लगाए जाएंगे। समीक्षा बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने फ्लोमीटर लगाने को लेकर अलग-अलग समय सीमा तय की है। इसके अनुसार, 31 दिसंबर 2023 तक सभी प्राइमरी और सेकेंडरी नेटवर्क पर फ्लोमीटर लगा दिए जाएंगे।

सीएम अरविंद के जरीवाल ने फ्लोमीटर लगाने में हो रही देरी पर जताई नाराजगी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी जरूरी पाइप लाइनों के उपर फ्लोमीटर लगाने का काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फ्लोमीटर लगाने में हो रही देरी पर कडी नाराजगी जताई और सबको एक टाइम लाइन तय कर दी है। सीएम द्वारा तय टाइम लाइन के अंदर दिल्ली जल बोर्ड को प्राइमरी और सेकेंडरी यूजीआर पर फ्लोमीटर लगाने होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी फ्लोमीटर का डेटा सेंट्रल लोकेशन भी प्रदर्शित किया जाए, ताकि उसकी नियमित निगरानी कर पानी के असमान वितरण को कंट्रोल किया जा सके।

सीएम अरविंद के जरीवाल ने डीजेबी को दी ये टाइम लाइन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्लोमीटर लगाने का काम पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय कर दी है और दिल्ली जल बोर्ड को इसी समय सीमा के अंदर हर हाल में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। सीएम द्वारा तय टाइम लाइन के अनुसार, अगले 22 दिनों के अंदर बिड के लिए आवेदन ले लिए जाएंगे और 20 अगस्त 2023 तक काम का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके अलावा, मटेरियल की आपूर्ति जैसे-जैसे होती जाएगी, उसी के समानांतर फ्लोमीटर स्टॉल किए जाएंगे।

# दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच फिर गैंगवार, 21 कैदी घायल

**नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता**

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच एक बार फिर गैंगवार हुई है। इसमें करीब 21 कैदी घायल हो गए।

जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, तिहाड़ जेल संख्या-8 में कैदी आपस में भिड़ गए। इस दौरान मारपीट में कई कैदियों ने खुद को घायल कर लिया है।

बता दें कि कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तिहाड़ में चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से जेल के वार्डों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

इनमें जनरल वार्ड, स्पेशल सिक्योरिटी वार्ड व हाई रिस्क सिक्योरिटी वार्ड शामिल हैं। कुल 975 कैमरों से जेल की निगरानी की जा रही है। साथ ही 80 अधिकारियों के अलावा एक हजार से अधिक जेलकर्मी तैनात हैं।

जेल में कैदियों की हो चुकी है हत्या

देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार तिहाड़ जेल इन दिनों अपराध का गढ़ बन गई है। जेल अंदर से आए दिन गैंगवार और झड़प के मामले सामने आते रहते हैं। इतना ही नहीं हाल ही में जेल के भीतर कैदियों की बेरहमी से हत्या की भी खबरें सामने आई हैं। ऐसी वारदातों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि जेल की सुरक्षा केवल कागजी तौर पर ही दुरुस्त है। उल्लेखनीय है कि 2 मई को तिहाड़ जेल की संख्या-तीन में कुछ लोगों ने रोहिणी कोर्ट शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर सूए से ताबड़तोड़ 92 बार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था।

इससे पहले अप्रैल माह के दूसरे हफ्ते में जेल संख्या तीन में बंद कैदी प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई थी। प्रिंस कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिला था।

# नीतीश की मुहिम को लग सकता है बड़ा झटका, विपक्ष की बैठक से पहले आप ने कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम

**नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता**

पटना में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 23 जून को होने वाली विपक्षी पार्टियों की महाबैठक से पहले ही विपक्षी एकता में सेंध लगती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का दावा है कि आप ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है कि वह अध्यादेश पर आप का समर्थन करे वरना वह बैठक का बायकॉट करेगी।

दरअसल आम आदमी पार्टी चाहती है कि 23 जून की बैठक में दिल्ली के लिए सेवा क्षेत्र में लाए गए केंद्र के अध्यादेश पर सबसे पहले चर्चा हो और सभी पार्टियां अध्यादेश के मुद्दे पर आप का समर्थन करें। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अब तक अपना पक्ष साफ नहीं किया है। इसे लेकर कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेता शुरू से ही अध्यादेश का विरोध करने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि वह अध्यादेश के खिलाफ नहीं हैं। अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांग चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई समय नहीं मिला। कांग्रेस ने अब तक नहीं दिया है केजरीवाल को मिलने का समय इसी के चलते बीते कुछ दिनों से लगातार केजरीवाल यह बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को उनका समर्थन करना चाहिए वरना अन्य राज्यों में भी दिल्ली जैसा हाल हो सकता है। इसके लिए केजरीवाल विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी भी लिख चुके हैं कि वह कांग्रेस से आप के समर्थन के लिए कहें। ऐसे में बैठक से एक दिन पहले सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है कि वह अध्यादेश पर दिल्ली का साथ दे वरना आप बैठक का बायकॉट कर देगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिया ये जवाब कांग्रेस नेता व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अगर वो (केजरीवाल) मीटिंग में नहीं आते तो उन्हें कोई मिस नहीं करेगा। हमें हमेशा से पता था कि वो इस बैठक में भाग न लेने के बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्हें जरूर अपने आकाओं से भी आदेश मिला होगा कि इस बैठक में भाग न लें।

# स्कूलों में छात्रों के लिए बनेंगे परामर्श कक्ष

नई दिल्ली। छात्रों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए सभी सरकारी स्कूलों में परामर्श (काउंसलिंग) कक्ष बनेंगे। छात्रों के स्वास्थ्य से लेकर करियर संवारने के लिए काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग के एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो (ईवीजीसी) ने इसका सर्कुलर जारी किया है। विभाग ने स्कूलों में ईवीजीसी के 500 पद पुनः आवंटित किए हैं। ईवीजीसी की तैनाती स्कूलों में की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से क्लस्टर स्कूल व्यवस्था बंद कर दी गई है। स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि काउंसलिंग कक्ष का उचित प्रावधान किया जाए। कक्ष सभी जरूरी संसाधनों से सुसज्जित हो। उसको छात्रों के अनुकूल तैयार करें, जिसमें संबंधित सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाए। ईवीजीसी को कक्षा संबंधी गतिविधि के लिए रोजाना चार पीरियड आवंटित किए गए हैं। सर्कुलर के अनुसार शिक्षक छात्रों के अनुशासन, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक संबंधी मुद्दे, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें सहित दूसरे मामले ईवीजीसी के पास भेजेंगे। उस आधार पर छात्रों की काउंसलिंग होगी, जिसका ईवीजीसी को रिकॉर्ड रखना होगा। उसका फॉलोअप भी लिया जाएगा। आखिर छात्र में कितना सुधार हुआ। ईवीजीसी कक्षा में छात्रों से पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, जिसकी रिपोर्ट हर महीने जिला काउंसलर प्रभारी को भेजी जाएगी। स्कूल प्रमुखों को निर्देश है कि वह ऐसे ईवीजीसी का चयन करें, जो छात्रों के निजी और भावनात्मक मुद्दों को समझे। जामा मस्जिद स्थित राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर-एक के प्रधानाचार्य गय्यूर अहमद ने बताया कि छात्रों के करियर सहित दूसरी समस्याओं के निदान के लिए ईवीजीसी काउंसलर की मदद ली जाती है।

# दिल्ली मेट्रो ने भरी रफ्तार, 16 मिनट में तय होगा नई दिल्ली से आईजीआई एयरपोर्ट का सफर

**नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता**

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बुधवार को एयरपोर्ट लाइन पर मेट्रो की गति को बढ़ा दी है। आईजीआई एयरपोर्ट के माध्यम से द्वारका सेक्टर-21 से जोड़ने वाली 23 किमी लंबी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (एईएल) पर मेट्रो ट्रेनों की गति अब 100 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटे कर दी गई है। इसके साथ डीएमआरसी ने 110 किमी प्रति घंटे की उल्लेखनीय गति हासिल करके भारतीय मेट्रो क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित किया है। साथ ही देश में सबसे तेज़ मेट्रो प्रणालियों में से एक होने का गौरव बरकरार रखा है। परिचालन गति में 110 किमी प्रति घंटे की वृद्धि के साथ यात्री अब लगभग 16 मिनट में नई दिल्ली से हवाई अड्डे (टी-3) तक पहुंच सकते हैं। इस गति वृद्धि ने हवाई अड्डे को शहर के केंद्र राजीव चौक के बहुत करीब ला दिया है, जहां अब 15 मिनट के भीतर पहुंचा जा सकता है। वर्तमान वृद्धि के बाद नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन तक यात्रा का कुल समय लगभग 20 मिनट होगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में 120 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा लागू होने के बाद पूरे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, एईएल पर कुल यात्रा का समय घटकर केवल 19 मिनट रह जाएगा। यह उपलब्धि डीएमआरसी की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। हाई-स्पीड यात्रा और हवाई अड्डे तक परेशानी मुक्त कनेक्टिविटी का संयोजन यात्रियों को एक सुविधाजनक और किफायती विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा हवाई अड्डे पर आगमन के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को अक्सर पार्किंग स्थान खोजने और महंगे पार्किंग शुल्क का भुगतान करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। मेट्रो का विकल्प चुनकर यात्री न केवल आरामदायक और किफायती यात्रा का आनंद ले सकते हैं, बल्कि हवाई अड्डे पर पार्किंग से जुड़ी असुविधाओं से भी बच सकते हैं। डीएमआरसी ने हाल ही में क्यूआर कोड और व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग के माध्यम से तेज और कैशलेस टिकटिंग विकल्पों के संदर्भ में यात्री सुविधा के लिए भी उपाय किए हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मेट्रो ने 22 मार्च, 2023 को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की परिचालन गति 90 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 100 किमी प्रति घंटे कर दी थी। बाद में आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ट्रेनों की गति 110 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 120 किमी प्रति घंटे कर दी जाएगी।

# भाजपा एक चुनावी हिन्दू पार्टी, चुनाव खत्म होते ही हिंदू मंदिरों पर करती है हमला- प्रियंका कक्कड़

दिल्ली के मंडावली में गुरुवार को पुलिस द्वारा प्राचीन मंदिर तोड़े जाने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा और एलजी को आडे हाथ लिया। पार्टी मुख्यालय मे आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड ने विधायक कुलदीप कुमार और पूर्व विधायक नितिन त्यागी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर भाजपा को हिंदू विरोधी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा एक चुनावी हिन्दू पार्टी है। जब चुनाव आता है तो खुद को हिन्दुत्व हितैषी बताती है और चुनाव खत्म होते ही हिंदू मंदिरों पर हमला करने लगती है। भाजपा के इशारे और एलजी के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने आज मंडावली में एक प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि एलजी दिल्ली को भी मणिपुर बनाना चाहते हैं। प्रियंका कक्कड ने कहा कि तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मंदिर तोडने की फाइल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इसके बाद एलजी ने उनको दरकिनार कर मंदिरों को तोडने का आदेश जारी किया और तब से दिल्ली में कई प्राचीन मंदिर तोड़े जा चुके हैं। पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का फरवरी 2023 का एक वीडियो दिखाकर बताया कि कैसे तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा द्वारा दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगाड़ने के मंसूबों को उजागर किया था। आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मंदिरों को तोड़ने वाली फाइल को बिना साइन किए एलजी को पास वापस भेज दी थी। क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी मंदिर के टूटने से उन क्षेत्रों में माहौल बिगड़ सकता है। इस पर एलजी ने मंदिरों को तोड़ने का प्लान न केवल पास किया, बल्कि यह भी आदेश दिया है कि मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थान को तोड़ने से संबंधित फाइल अब से दिल्ली सरकार के पास नहीं जाएगी। फाइल सीधे एलजी के पास आएगी। इसके बाद बहादुर शाह जफर मार्ग में 150 साल पुराना प्रचीन शिव मंदिर, राजेंद्र नगर में 50 साल पुराना हनुमान मंदिर, सरोजनी नगर में प्राचीन हनुमान मंदिर और श्रीनिवासपुरी में नील कंठ मंदिर तोड़ दिया गया। प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आज मंडावली में भाजपा की दिल्ली पुलिस एक मंदिर को सुबह से तोड़ रही है। भाजपा एक एंटी हिंदू व चुनावी हिंदू पार्टी है।

# दिल्ली हवाईअड्डे पर 38 करोड़ की कोकीन की तस्करी के आरोप में केन्याई महिला गिरफ्तारः सीमा शुल्क

नई दिल्ली। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 38 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन की तस्करी कर रही एक केन्याई महिला को गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कोकीन शराब की बोतलों में छिपा कर रखी गई थी।

आरोपी, अदीस अबाबा होते हुए केन्या से आयी थी। सोमवार को हवाईअड्डे पर उतरने के बाद उसे रोका गया और जांच की गई। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के बैग से मिली तीन शराब की बोतलों में 2.5 किलोग्राम कोकीन छिपा कर रखी गयी थी। उन्होंने कहा कि यात्री को यह बैग नैरोबी में दिया गया था जिसे दिल्ली पहुंचकर एक व्यक्ति के हवाले करना था।

अधिकारी ने बताया कि यात्री को गिरफ्तार कर 38.05 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन जब्त कर ली गई। उन्होंने कहा कि आरोपी को मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

उल्लेखनीय है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने हवाईअड्डे पर 15 जून को एक अन्य केन्याई महिला को 13 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन की तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया था। यह कोकीन शराब की दो बोतलों में घोली गई थी।

इस बीच अधिकारियों ने हवाईअड्डे पर काम कर रही निजी एजेंसियों के दो कर्मचारियों के खिलाफ 2.42 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी करने को लेकर दो अलग मामले दर्ज किए। सीमा शुल्क ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ह्रदो लोगों की तलाशी के दौरान उनके पास से 4.63 किलोग्राम सोना बरामद किया गया जिसकी कीमत तकरीबन 2.42 करोड़ रुपये है। तलाशी के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

# दिल्ली में 24 घंटे बिजली सप्लाई, मुफ्त बिजली योजना रोकना चाहती है भाजपा

**नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता**

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा टकराव दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के नए चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर है।

इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की बिजली मंत्री आतिशी ने आज गुरुवार को कहा कि कल रात 10 बजे भाजपा शासित केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार पर एक और हमला किया है।

उन्होने कहा कि रात के अंधेरे में एक और अधिसूचना जारी कर गैरकानूनी व असंवैधानिक तरीके से डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई। यह दिल्ली की बिजली व्यवस्था को ध्वस्त करने, सस्ती और मुफ्त बिजली रोकने के लिए है।

भाजपा दिल्ली को बिजली आपूर्ति के मामले में नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसा बनाना चाहती है, जहां बिजली कटौती की गंभीर समस्या है। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार को लेकर पिछले कई वर्षों से अदालत में लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि भूमि, कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा अन्य विषयों पर निर्वाचित सरकार की सलाह जरूरी है।

आतिशी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 21 जून को दिल्ली सरकार द्वारा डीईआरसी के चेयरमैन के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा का नाम एलजी को भेजा गया। इसे नहीं मानते हुए उमेश कुमार को चेयरमैन बना दिया।

यह असंवैधानिक व दिल्ली के लोगों के खिलाफ फैसला है। यह दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए है। दिल्ली के लोग प्रत्येक बार अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से सत्ता में भेजते हैं। भाजपा को लगता है कि यह दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी गलती है। इस गैरकानूनी फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार लड़ाई लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

दिल्ली में मिलती है सबसे सस्ती बिजली- आतिशी

आतिशी ने कहा कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। यहां 300 यूनिट तक बिना सब्सिडी बिजली की दर प्रति यूनिट 4.50 रुपये है।

वहीं, असम में 300 यूनिट तक 8.20 रुपये प्रति यूनिट, उत्तर प्रदेश में 6.50 रुपये, मध्यप्रदेश में 6.20 रुपये और महाराष्ट्र में 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलती है।

2015 से नहीं बढ़ी बिजली की दरें

केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली में प्रत्येक छह माह में बिजली के बिल बढ़ जाते थे। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद 2015 से 2023 तक बिजली की दरें नहीं बढ़ी है।

दिल्ली में 41 लाख परिवारों को मिलती मुफ्त बिजली- आतिशी

आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली में 41 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली मिलती है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली में 24 घंटे बिजली आपूर्ति रोकने, 41 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली रोकने, भाजपा शासित राज्यों की तरह महंगी बिजली देने के लिए काम कर रही है।

# जामिया कुलपति ने जारी किया जर्नल तदरीस नामा

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने गुरुवार को एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स (एपीडीयूएमटी), जामिया के जर्नल ह्यातदरीस नामाह्न का 9वां अंक जारी किया। उन्होंने व्यापक स्तर पर इसे कवर करने वाले एक अच्छे जर्नल के प्रकाशन के लिए अकादमी के अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अंक में शामिल लेखों को पढ़कर उर्दू शिक्षक आत्मज्ञान हासिल करेंगे। उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना जामिया के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने और अकादमी को अपना दायरा बढ़ाने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि अकादमी ने हाल में एससीईआरटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और यह समय की मांग है कि उसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों के एससीईआरटी के साथ भी समझौते पर विचार करना चाहिए। अकादमी को अकादमिक पुस्तकों के अनुवाद पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो शिक्षकों को उर्दू में विभिन्न विषयों को पढ़ाने में मददगार होगी। तदरीस नामा के वर्तमान अंक में गजल,नाटक और शोकगीत की शिक्षा से संबंधित लेख हैं।

**JOTINDRA STEEL & TUBES LIMITED**

Regd. Office & Works: 14/3, Mathura Road, Faridabad- 121 003 ( Haryana) India
Phone : +95-129-2477800,2477806, Fax : +95-129- CIN: L27104HR1970PLC005240
E-mail : jotindra@jotindra.com;Web-site:www.jstltd.com

**NOTICE OF POSTAL BALLOT/E-VOTING**

**NOTICE** is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108, 110 of the Companies Act, 2013 (**"the Act"**), and other applicable provisions of the Act read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (**"the Rules"**), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"Listing Regulations"**), Secretarial Standard on General Meetings (**"SS-2"**) issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), guidelines prescribed by the Ministry of Corporate affairs (**"MCA"**), Government of India, for holding general meeting / conducting postal ballot process through electronic voting (**remote e-voting**) vide General Circular Nos. 14/2020 dated 08.04.2020 and 17/2020 dated 13.04.2020 read with other relevant circulars, including General Circular No.20/2021 dated 08.12.2021, issued by the MCA (**"MCA Circulars"**), the following items of special business are proposed to be passed by the Members of Jotindra Steel and Tubes Limited (**"the Company"**) by means of Postal Ballot through remote e-voting (**"e-voting"**).

The remote e-voting period commences from 09.00 a.m. (IST) on Monday, June 19, 2023 and ends at 05.00 p.m. (IST) on Tuesday, July 18, 2023. Members are requested to peruse the proposed resolution along with the explanatory statement, carefully read the instructions in the Notes to this Notice and cast their vote electronically by indicating Assent (For) or Dissent (Against) for the said Resolution not later than 05:00 p.m. (IST) on Tuesday, July 18, 2023 (the last day to cast vote electronically).

The resolution, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on Tuesday, July 18, 2023 i.e. the last date specified for e-voting.

**SPECIAL BUSINESS**

**Appointment of Mr. SATVINDER ARORA (DIN: 10098409) as an Independent Director of the Company for a term of 5 (five) years**

**Notes:**

1. The Explanatory Statement pursuant to Section 102 read with Section 110 of the Act setting out material facts pertaining to the resolution, is annexed hereto for your consideration and forms part of this Notice.
2. The relevant details, pursuant to the provisions of SEBI LODR and SS-2, in respect of Director seeking appointment are also annexed hereto.
3. The Notice is being sent to all the members, whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Thursday, June 09, 2023. In compliance with MCA Circulars, the Notice is being sent to members only in electronic form to the e-mail addresses registered with their Depository Participants (in case of electronic shareholding) / the Company's Registrar and Transfer Agent (in case of physical shareholding). Physical copies of the Notice are not being sent to the members for this Postal Ballot. Therefore, those members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to get their e-mail addresses registered by following the procedure given below in e- voting instructions.
4. The Notice is also available on the website of the Company at **https://www.jstltd.com/**, on the website of stock exchange i.e. Metropolitan Stock Exchange **https://www.msei.in/** respectively and on the website of the NSDL i.e. **www.evoting.nsdl.com**.
5. In compliance with the provisions of Sections 108 and 110 of the Act, read with the Management Rules and Regulation 44 of SEBI LODR, the Company is offering e-voting facility to all the members of the Company to enable them to cast their votes electronically. The Company has engaged the services of NSDL to provide e-voting facility to its members. The instructions for e-voting are annexed to this Notice.
6. The voting rights of the members shall be in proportion to their holding of Equity Shares with the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, June 09, 2023 (**"Cut-Off date"**). Only those members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off date will be entitled to cast their votes by e-voting. A person who is not a member as on the Cut-Off date should treat this Notice for information purposes only.
7. Facility to exercise vote by Postal Ballot by voting through electronic means will be available during the following period:
   - Commencement of voting: Monday, 19.06.2023 at 09:00 am (IST) End of voting: Tuesday, 18.07.2023 at 05:00 pm (IST) (both days inclusive).
   - The facility for voting through electronic means will be disabled for voting by NSDL upon expiry of the aforesaid voting period.
8. All the relevant documents referred to in this Notice and explanatory statement shall be available for inspection by the members through electronic mode up to the last date specified for e-voting. The members may write to the Company at jotindra@jotindra.com in this regard.
9. A member cannot exercise his/her vote through proxy on postal ballot. However, corporate and institutional members shall be entitled to vote through their authorized representatives. Corporate and institutional members are requested to provide a proof of authorization (board resolution/authority letter/power attorney, etc.) in favour of their authorised representatives to the scrutinizer through e-mail to csjyotiarya@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
10. Further, SEBI vide notification dated January 24, 2022 has amended Regulation 40 of SEBI LODR and has mandated that all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialization, members are therefore advised to dematerialize the shares held by them in physical form.

**By order of the Board of Directors**
**FOR JOTINDRA STEEL & TUBES LIMITED**
**Sd/-**
**AKHIL SUREKA**
**(MANAGING DIRECTOR)**
**DIN: - 00060206**